रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार , 30 अप्रैल, 2026

वर्ष 02 | अंक 108 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

● विधानसभा चुनाव 2026- एग्जिट पोल

बंगाल में भाजपा ने किया खेला, दूसरे नंबर पर टीएमसी

असम में फिर भाजपा, एनडीए को 88-100 सीटें, कांग्रेस को 24-36 सीटों का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। दो चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.88 फीसदी मतदान हुआ। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चाणक्य के एग्जिट पोल आए सामने आ गए हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है।

पश्चिम बंगाल

एजेंसी	टीएमसी+	भाजपा	अन्य
मैट्रिज	125-140	146-161	6-10
पोल डायरी	99-127	142-171	5-9
चाणक्य स्ट्रैटजीज	130-140	150-160	6-10
प्रजा पोल	85-110	178-208	0-0
पीपल्स पल्स	177-187	95-110	1-4
पीमारक्यू	118-138	150-175	2-6

तमिलनाडु में इस बार डीएमके की सरकार

एवीपी के एग्जिट पोल में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इस एग्जिट पोल के अनुसार, डीएमके को 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है।

पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ में की पूजा, लहराया त्रिशूल

● 108 बटुकों ने शंखनाद किया, भाजपा कार्यकर्ता नाचते दिखे

वाराणसी (एजेंसी)। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा-अर्चना की। पांच पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत की। इससे पहले, पीएम के रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। प्रधानमंत्री का जगह-जगह स्वागत किया

गया। काफिले पर फूल बरसाए गए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि, वह कहीं रुके नहीं। काशी से पीएम हरदोई के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।

पीएम ने सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण

● अखिलेश पर बरसे, कहा-यूपी को गाली देने वालों के साथ खड़ी है सपा

हरदोई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद 12 घंटे का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेस-वे 12 जिलों से गुजरेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। पहले पड़ोस के जिलों तक जाना भी मुश्किल होता था। अब यूपी में 21 एयरपोर्ट हैं। इनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारा यूपी भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया के ऊपर फिल्में बनती थीं। जिन सपाइयों के हाथ से सत्ता गई, उन्हें यूपी की प्रगति पसंद नहीं आ रही। प्रधानमंत्री ने कहा-समाजवादी पार्टी विकास विरोधी तो है ही, नारी विरोधी भी है। पिछले दिनों संसद में सपा ने बिल का विरोध किया।

पांच साल के भीतर बनकर तैयार हो गया एक्सप्रेसवे

पीएम मोदी ने कहा-दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार गंगा एक्सप्रेसवे पांच साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। फरुर्खाबाद लिंक के जरिये इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन के सरकार के काम करने का तरीका।

पहले सड़क बनने के लिए लोग दशकों करते थे इंतजार

प्रधानमंत्री ने कहा- कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का मौका मिला था। ये एक्सप्रेसवे आधुनिक भारत की हस्तरेखाएं हैं। अब वह दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। एक बार घोषणा हो गई तो सालों तक फाइलें चलती थीं। सरकारें आती रहती थीं पर काम का पता नहीं चलता था। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण होकर ही रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकारों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा-पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की। इस कारण किसान परेशानियों में उलझ कर रह गए। किसानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी।

आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें यूपी में बनती हैं

प्रधानमंत्री ने कहा-पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था। आज यूपी एक ट्रिलियन इकॉनामी बनने जा रहा है। यूपी के युवाओं का इस्तेमाल हम अच्छे तरह से कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती है, उसे आज इन्वेस्ट यूपी के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल बनते हैं तो यूपी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी यूपी तेजी से स्थान बना रहा है। आज देश के दो डिफेंड कॉरीडोर में से एक यूपी में है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज यूपी में बनती हैं। पीएम मोदी ने भूमि को प्रणाम किया।

प्रदेश के 14 जिलों में मखाना उत्पादन बढ़ाने पर जोर

● सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा-फ्लोरीकल्चर सेंटर बनाएंगे

● मुख्यमंत्री बोले-उज्जैन में फूलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्लोरीकल्चर खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलें कम जमीन में अधिक आय का प्रभावी माध्यम हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जाए। मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सीजनल और उद्यानिकी फसलों के साथ जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाए। प्राकृतिक

खाद के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 40 विभागीय नर्सरियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। वहीं प्रेसराइज्ड इरीगेशन वाले जिलों में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार किया जा रहा है। बैठक में उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मसाला फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पुष्प और सब्जी उत्पादन में तीसरे तथा फल उत्पादन में चौथे स्थान पर प्रदेश है। बैठक में यह भी बताया गया कि मखाना क्षेत्र विस्तार योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से परियोजना लागत पर 40 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है।

ईवीएम में भाजपा के बटन पर लगा मिला टेप, बवाल

● बंगाल में जमकर कोहराम, वोटिंग रुकी, ईसी बोला-दावा सही तो दोबारा मतदान

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले फाल्टा में भाजपा ने ईवीएम पर भाजपा के विकल्प के सामने टेप लगे होने की शिकायत की है। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जिन

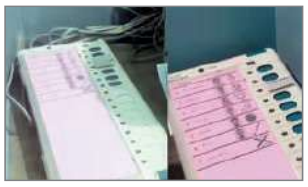

पोलिंग बूथ पर किसी भी ईवीएम बटन पर टेप लगा पाया जाएगा, वह दोबारा मतदान होगा। विवाद ज्याद बढ़ने के बाद कई पोलिंग बूथों प वोटिंग रोक दी गई है। सीईओ ने कहा, अगर किसी बटन पर टेप लगाए जाने की रिपोर्ट आती है, त उसकी जांच की जानी चाहिए और उसे नोट किया जाना चाहिए। अगर यह सच पाया जाता है, तो उन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि दूसरे फेज के दौरान, डायमंड हार्बर के फाल्टा में कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पार्टी के उम्मीदवार को चुनने से रोका गया।

देपालपुर में खाद-बीज दुकानों की हड़ताल

कंपनियों की मनमानी के खिलाफ बंद रहा कारोबार

मांगें नहीं मानीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन

देपालपुर-नगर में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वाले व्यापारियों ने सोमवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दुकानों के शटर बंद रहे, जिससे किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंदौर सहित कई जिलों में विक्रेताओं ने अपना कामकाज बंद रखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम तहसीलदार संगीता गोलिया को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि फर्टिलाइजर कंपनियां लगातार मनमानी कर रही हैं और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

राज्यभर में बंद रहीं खाद-बीज की दुकानें

27 अप्रैल को मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। यह हड़ताल एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन

के आह्वान पर की गई थी। इंदौर जिले में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जहां लगभग अधिकांश विक्रेताओं ने अपना कारोबाद बंद रखा।

तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन

देपालपुर में बड़ी संख्या में व्यापारी एमडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और उर्वरक मंत्री के नाम दिया गया। तहसीलदार संगीता गोलिया को सौंपे गए इस ज्ञापन में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा।

'कंपनियों पर कार्रवाई नहीं, हमें परेशान किया जाता है'

एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानों से अधिकारी जांच के नाम पर दवाओं के सैंपल लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कंपनियों पर नहीं होती बल्कि हमें ही परेशान किया जाता है। उनके मुताबिक यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और अब व्यापारियों का सब्र जवाब दे रहा है।

सब्सिडी खाद के साथ जबरन खरीद का आरोप

व्यापारियों ने फर्टिलाइजर कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनियां सब्सिडी वाली खाद के साथ अन्य उत्पाद भी जबरन खरीदने के लिए दबाव बनाती हैं। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की 'जबरन लिंकिंग' को तुरंत बंद किया जाए और इसे अपराध घोषित किया जाए, ताकि पूरे देश में इस पर रोक लग सके।

देपालपुर में निकलीं गौ सम्मान आह्वान यात्रा,गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग

देपालपुर-नगर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ सुरक्षा की मांग को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई, यह यात्रा "गौ सम्मान आह्वान अभियान" के तहत गौ रक्षा दल के नेतृत्व में आयोजित की गई शोभायात्रा का शुभारम्भ शांति विहार कॉलोनी से हुआ जो नगर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए तहसील मुख्यालय पहुंची जहां तहसीलदार संगीता गोलिया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौवंश के संरक्षण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस अवसर पर महामंडलेश्वर भगवानदास जी महाराज, पुजारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित राजेश शास्त्री, जबरेश्वर सेना के संरक्षक

राजेंद्र चौधरी, पंडित भविष्य व्यास,पंडित गौरव व्यास सहित सेंकड़ों गौ भक्त उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर गौ संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए. ज्ञापन का वाचन महामंडलेश्वर भगवानदास जी महाराज ने किया इसमें वेद लक्षणा गौ माता और सभी देशी गौवंश की सेवा,सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सम्मान की मांग की गई।.

जनसुनवाई बनी सहारा : कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की तत्परता से गर्भवती महिला को मिली समय पर चिकित्सा सहायता

आदित्य शर्मा

प्रशासन की संवेदनशील पहल से सुरक्षित हुआ प्रसव
गायत्री ने जताई इच्छा - बेटी का नाम कलेक्टर श्री शिवम वर्मा रखें

इंदौर। राज्य शासन की #जनसुनवाई व्यवस्था एक बार फिर जरूरतमंद नागरिकों के लिए उम्मीद और राहत का माध्यम साबित हुई। आर्थिक तंगी और पारिवारिक सहयोग के अभाव में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही 9 माह की गर्भवती महिला गायत्री ने अपने पति के साथ 21 अप्रैल को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर सहायता की गुहार लगाई। गायत्री और उनके पति ने प्रशासन को बताया कि उनके पास प्रसव के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। पारिवारिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं तथा ससुराल पक्ष से सहयोग नहीं मिलने के कारण वे अत्यंत परेशान और असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे संवेदनशील समय में उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की अपेक्षा की। मामले की गंभीरता और मानवीय पक्ष को समझते हुए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। जिला प्रशासन की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही के परिणामस्वरूप गायत्री को समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के समन्वित प्रयासों से उनका सुरक्षित प्रसव कराया गया।

खुशी की बात है कि गायत्री ने एक स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया। इस सुखद अवसर पर परिवारजनों ने जिला प्रशासन, चिकित्सा दल एवं संबंधित

अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं के साथ सहयोग प्रदान कर उनका विश्वास मजबूत किया है। भावुक क्षण तब देखने को मिला जब गायत्री और उनके परिवार ने अपनी नवजात बेटी का नाम कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के हाथों रखने की इच्छा व्यक्त की। यह घटना जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली, जनसुनवाई व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा जरूरतमंद नागरिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का प्रेरणादायी उदाहरण बन गई है।

तप से हमारे सुप्त संस्कारों का जागरण होता है

तपस्या भी मानसिक, वाचिक और कर्म आधारित है। मन को सभी इंद्रियों व उनके सुख में जाने से रोकना मानसिक तप है। व्यर्थ नहीं बोलना और मौन रखना वाचिक तप है। किसी इच्छापूर्ति या पाने की आकांक्षा हेतु व्रत रखना या अपने शरीर को कष्ट देना जैसे हठयोग आदि सब शारीरिक तप है।

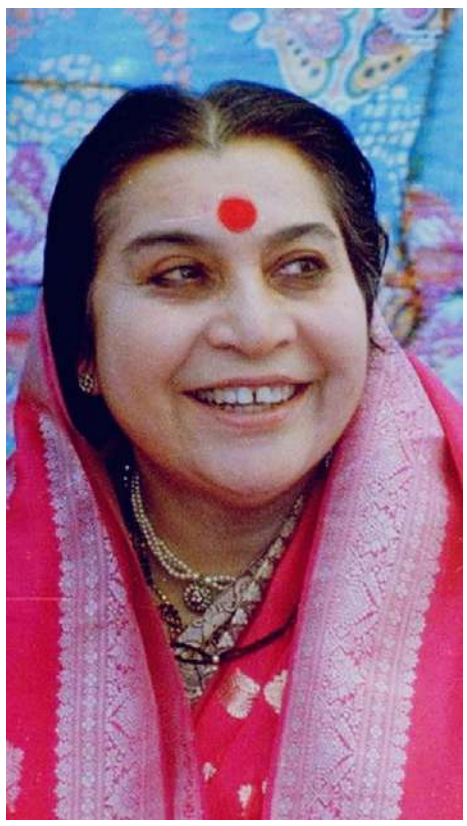

तप आध्यात्मिक जीवन की आधार-शिला है। 'तप आधार सब सृष्टि भवानी' लिखकर संत तुलसी ने इसे महिमा मंडित किया है। तपस्वी अपने जीवन की दशा स्वयं निर्धारित करते हैं, जबकि सामान्य व्यक्तियों का जीवन पूर्णतः परिस्थितियों के अधीन होता है। तपस्वी तप की ऊर्जा से परिस्थिति की प्रतिकूलता को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। वस्तुतः तप करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसकी कुछ मर्यादाएं हैं। सनक में आकर कुछ भी करते रहने का नाम तप नहीं है। नमक न खाना, नंगे पांव चलना, भूखे रहना आदि क्रियाओं से शारीरिक कष्ट तो अवश्य होता है, किंतु कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होता। सुनिश्चित संकल्प के साथ तप पर अमल गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। तप से हमारे सुप्त संस्कारों का जागरण होता है और यह जागरण हमारे आध्यात्मिक विकास को गति देता है। तप का उद्देश्य मात्र ऊर्जा का अर्जन ही नहीं, उस ऊर्जा का संरक्षण व सुनियोजन भी है। जो अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर लेता है वह सामर्थ्यवान हो जाता है। तप कोई चमत्कार न होकर स्वयं का परिष्कार है।

सहज योग एक ऐसा ही परिष्कार है वहां चमत्कार स्वतः तो होते हैं पर तपस्या से, और यह तपस्या है ध्यान। सहज योग की प्रणेता हमारी परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने ध्यान की जो विधि बताई है वो आसान है समझने में। लेकिन सहज योग की मर्यादाओं का पालन करते हुए दिन में दो बार ध्यान में बैठकर सिखाई गई विधि से ध्यान धारणा करना है। धीरे - धीरे नाड़ियां शुद्ध होती हैं और हम चैतन्य के प्रवाह(हथेली में ठंडी हवा का बहाव) को महसूस करने लगते हैं। यही चैतन्य हमारी जिंदगी में आश्चर्यजनक बदलाव लाते हैं। हम स्वयं को भी निरोगी रख पाते हैं और दूसरों को भी। ध्यान धारणा से जागृत चक्र हमारे सद्गुणों को भी जागृत करते हैं। गृहस्थ जीवन जीते हुये अपने परिवार और समाज के प्रति संपूर्ण दायित्व निभाते हुये सहज योगी बना जा सकता है। अहंकार तप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अतः ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना ही पड़ता है। तपस्या करने में असुर सबसे आगे रहे हैं। तपस्या के द्वारा वे भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त करते रहे हैं। आलस्य को त्यागकर वर्षों तक कठोर तपस्या करने का साहस उनमें होता है, किंतु अपने अहंकार का त्याग न कर पाने के कारण वे तप से प्राप्त ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। सहज योग हमें सकारात्मक उर्जा देता है। नकारात्मक सोच के साथ भी यदि कोई सहज योग का अभ्यास करता है तो उसके सोच में भी बदलाव आने लगता है। यह बदलाव ही हमें जीवन की सही दिशा देता है। सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा यूट्यूब चैनल लर्निंग सहजयोगा से प्राप्त कर सकते हैं। सहज योग पूर्णतया निशुल्क है।

इंदौरः चंदननगर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2.160 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चंदननगर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप वर्मा (50) निवासी लाल बहादुर शास्त्री नगर, केसरबाग रोड को इंद्रप्रस्थ सिंदोड़ा क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से करीब 2.160 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये आंकी गई है, बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और सस्ते दामों में गांजा खरीदकर महंगे दामों में बेचता था। साथ ही जल्दी पैसे कमाने और कर्ज चुकाने के उद्देश्य से इस अवैध कारोबार में लिप्त था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत 3 प्रकरण और एक मारपीट का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 550/26, धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही उसके नेटवर्क और अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ जारी है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी तिलक करोले के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई।

सराहनीय भूमिकाः इस कार्रवाई में उनि सौरभ कुशवाह, उनि सेवना सिंह, प्रधान आरक्षक प्रदीप, बलराम चौहान, जितेंद्र सोलंकी, आरक्षक अनिल मकावाना एवं सुनील सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इंदौर में पक्षियों के लिए

'सकोरे और दाना' वितरण अभियान का आगाज़

श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की सराहनीय पहल

इंदौर। भीषण गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, पक्षियों के संरक्षण के लिए श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पक्षियों के लिए 5100 सकोरे (मिट्टी के बर्तन) और दाना वितरण अभियान शुरू किया गया है।

इस अभियान का विधिवत शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण पटेल के कर-कमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति (महिलाएं) उत्साह के साथ आगे आईं और उन्होंने इस पुनीत कार्य में जुड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समाज सेवी मदन परमालिया, प्रतिश राजू, जगदीश जोशी और मनोज पाटीदार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ट्रस्ट का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि बढ़ती गर्मी में उन्हें राहत मिल सके।

अचानक निरीक्षण से उपार्जन केंद्रों में बढ़ेगी सख्ती, मुख्यमंत्री मोहन यादव कभी भी कर सकते हैं दौरा

सलीम हूसैन

झाबुआ। मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को लेकर अब प्रशासनिक सख्ती और बढ़ने वाली है। मोहन यादव आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। यह निरीक्षण पूरी तरह से अचानक होगा, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसी भी समय, किसी भी जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर उतर सकता है, जिससे प्रशासनिक अमले में पहले से ही सतर्कता बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और किसानों के हित में संचालित हो। निरीक्षण के दौरान वे सीधे किसानों से संवाद करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शासन और प्रशासन द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं।

प्रदेश सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई व्यवस्थाएं लागू की हैं। केंद्रों पर पीने के पानी, छायादार बैठने की व्यवस्था और अन्य जनसुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसानों को इंतजार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी एक केंद्र तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने की सुविधा दी गई है, जिससे भीड़ का दबाव कम हो सके। तौल प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी गई है और आवश्यकता अनुसार जिलों को इसे और बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा बारदाने, हम्माल, तुलावटी, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और साफ-सफाई के लिए जरूरी संसाधन भी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उपार्जन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चल सके।

सरकार ने गुणवत्ता मानकों में भी कुछ राहत दी है। गेहूं के एफएक्यू मापदंड में शिथिलता देते हुए चमक विहीन गेहूं की सीमा 50 प्रतिशत तक कर दी गई है। इसी तरह सूकड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत तक कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक किसानों की उपज खरीदी जा सके। उपार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन प्रति केंद्र स्लॉट बुकिंग की सीमा 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दी गई है, जिसे जिले आवश्यकता अनुसार 3000 क्विंटल तक बढ़ा सकते हैं। इससे किसानों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया तेज होगी।

इस वर्ष किसानों से गेहूं की खरीदी 2585 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस जोड़कर कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है।

किसानों की सुविधा के लिए अब शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और उपार्जन कार्य जारी रहेगा, जिससे प्रक्रिया में किसी प्रकार का ठहराव न आए। सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए पोस्टर और बैनर भी उपार्जन केंद्रों पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आकस्मिक निरीक्षण को देखते हुए अब यह साफ है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

दोपहर में पहुंचे लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

आदित्य शर्मा

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य तेज गति से जारी है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज दोपहर लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पहुंचकर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में चल रही खरीदी प्रक्रिया, तौल व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कलेक्टर श्री रोशन राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।

किसानों से किया सीधा सवांद

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने मंडी में आए किसानों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। किसानों ने उपार्जन व्यवस्था को लेकर संतुष्टि व्यक्त की और बताया कि तौल एवं भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। किसानों के साथ बैठकर भोजन भी किया कलेक्टर श्री वर्मा ने किसान विश्राम गृह का भी निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कैंटीन में किसानों के साथ बैठकर भोजन भी किया और व्यवस्थाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की।

बुद्ध पूर्णिमा पर मेधावी छात्रों और प्राशासनिक सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं का होगा सम्मान

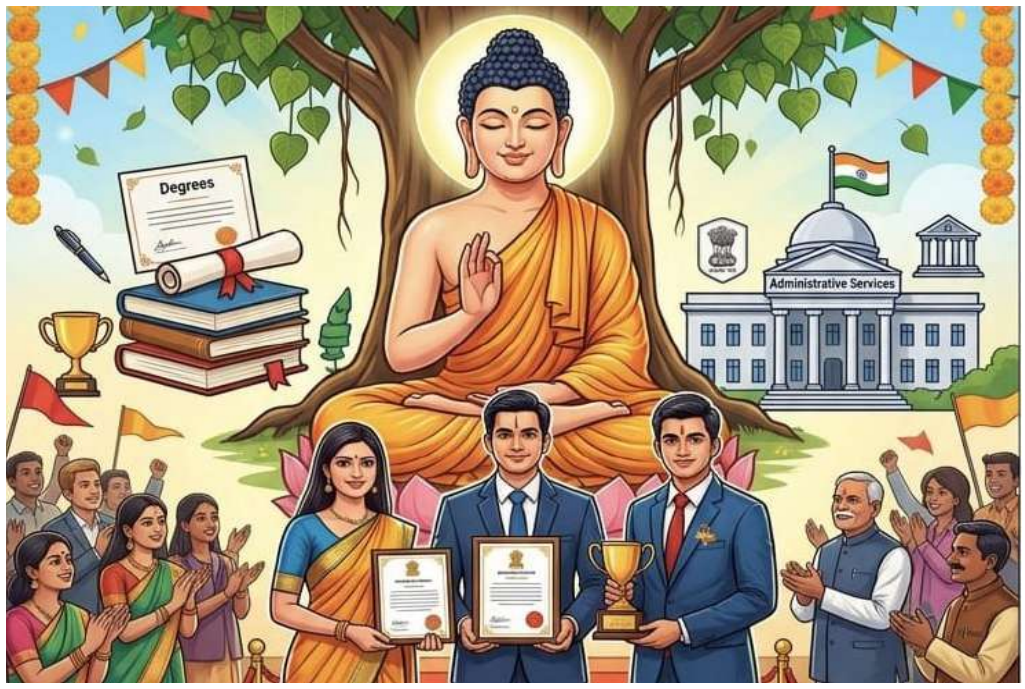

दिव्यानंद अर्गल

मेहगांव / भिंड । डॉ. अम्बेडकर समन्वय समिति, मेहगांव के तत्वावधान में तथागत गौतम बुद्ध की 2588वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर आगामी 1 मई को एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गल्ला मण्डी स्थित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आध्यात्मिक आश्रम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा, सेवा और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बुद्ध जयंती के इस शुभ अवसर पर सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए, इस उद्देश्य से उन्हें स्टेशनरी का वितरण किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का सम्मान किया जाएगा हाल ही में प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का विशेष अभिनंदन किया जाएगा, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके। डॉ. अम्बेडकर समन्वय समिति ने क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों, समाजसेवियों और छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर तथागत बुद्ध के विचारों को आत्मसात करें और प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें।

आईडीए की 3 टीपीएस योजनाओं में विकास तेज, मास्टर प्लान की सड़कों पर फोकस

पुरानी योजनाओं की अड़चनें दूर करने शासन से मांगा मार्गदर्शन

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की तीन टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। इन योजनाओं में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि शहर के सुनियोजित विस्तार के साथ यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सके। आईडीए द्वारा विकसित की जा रही टीपीएस योजनाएं शहर के बाहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। प्राधिकरण का कहना है कि मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों का निर्माण इन योजनाओं की आधारभूत जरूरत है, क्योंकि सड़क नेटवर्क तैयार होने के बाद अन्य विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आईडीए अध्यक्ष के अनुसार, तीनों टीपीएस क्षेत्रों में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सड़कों के निर्माण से न केवल इन क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, बल्कि आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इससे शहर के बाहरी हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधारभूत ढांचा

विकसित किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल नई योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं में आ रही तकनीकी और कानूनी समस्याओं के समाधान पर भी काम किया जा रहा है। कई परियोजनाएं भूमि, स्वामित्व, स्वीकृतियों और प्रक्रियागत अड़चनों के कारण प्रभावित रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। आईडीए अधिकारियों का मानना है कि शासन स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश मिलने के बाद लंबित मामलों का निराकरण तेजी से हो सकेगा। इससे न केवल रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि शहर के विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। प्राधिकरण का उद्देश्य टीपीएस योजनाओं के माध्यम से इंदौर का नियोजित विस्तार सुनिश्चित करना है, ताकि अनियंत्रित शहरीकरण पर रोक लगाई जा सके और शहर के नए क्षेत्रों में बेहतर सड़क, जल निकासी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकें। आईडीए का दावा है कि इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद इंदौर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

जल संकट के बीच टैंकर के पानी से धुलाई, कब जागेगा समाज

इंदौर में एक ओर नगर निगम भीषण गर्मी और जल संकट के बीच नागरिकों से पानी बचाने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई गरीब बस्तियां आज भी टैंकरों के सहारे जीवन जी रही हैं। ऐसे समय में निपानिया क्षेत्र की कुछ संपन्न सोसायटियों में टैंकर के पानी से फर्श और परिसर की धुलाई कराया जाना अत्यंत चिंताजनक है। जब जरूरतमंद परिवार पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हों, तब इस प्रकार जल का अपव्यय सामाजिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है। नगर निगम की जिम्मेदारी केवल पानी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग की निगरानी करना भी है। यदि जल संकट वास्तविक है, तो नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व है। पानी जीवन है, प्रदर्शन का साधन नहीं। यदि आज भी समाज नहीं चेता, तो आने वाला समय और अधिक कठिन होगा।

पैन कार्ड नियमों में बदलाव से नई कंपनियों का काम अटका

नए वित्त वर्ष में बनी कंपनियों के सामने बड़ी अड़चन, पैन नहीं बनने से कारोबार शुरू होने में देरी

इंदौर। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड नियमों में किए गए बदलाव ने नई कंपनियों और फर्मों के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया है। 1 अप्रैल से लागू नई प्रक्रिया के कारण नई कंपनियों के पैन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनका जीएसटी पंजीयन और कारोबार शुरू होना अटक गया है। व्यापारिक और कर सलाहकारों के अनुसार, हर साल अप्रैल में बड़ी संख्या में नई कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप इकाइयां पंजीकृत होती हैं। सामान्यतः इनके गठन के बाद सबसे पहला और जरूरी काम पैन कार्ड बनवाना होता है, क्योंकि इसी के आधार पर जीएसटी नंबर जारी होता है और उसके बाद ही बैंक खाते, बिलिंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो पाती हैं। इस बार स्थिति अलग है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब तक आधार कार्ड को जन्मतिथि और पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में आधार को इन दोनों उद्देश्यों के लिए मान्य दस्तावेज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

आधार अब केवल पहचान, जन्मतिथि और पते के लिए अलग दस्तावेज जरूरी- नए नियमों के अनुसार अब पैन कार्ड आवेदन में जन्मतिथि के प्रमाण के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पते के प्रमाण के लिए पासपोर्ट सहित अन्य अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यानी अब केवल आधार कार्ड के सहारे पैन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इससे खासतौर पर नई कंपनियों के प्रमोटर्स, पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स को दस्तावेज जुटाने में अतिरिक्त समय लग रहा है। कई मामलों में आवेदन दस्तावेज सत्यापन के स्तर पर अटक रहे हैं।

एक सप्ताह की जगह महीना, फिर भी नहीं आया पैन- अब तक पैन कार्ड आवेदन के बाद सामान्यतः 5 से 7 कार्य दिवस में पैन जारी हो जाता था। इससे नई फर्में जल्दी जीएसटी नंबर लेकर कारोबार शुरू कर देती थीं। लेकिन इस बार अप्रैल में आवेदन करने वाले कई आवेदकों को अभी तक पैन आवंटित नहीं हो पाया है। एक माह बीतने को है, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इसका सीधा असर नई कंपनियों के संचालन पर पड़ रहा है।

जीएसटी नहीं, तो कारोबार नहीं- सीए कीर्ति जोशी के अनुसार नई कंपनी या फर्म के गठन के बाद पैन कार्ड सबसे बुनियादी दस्तावेज होता है। पैन के बिना जीएसटी पंजीयन संभव नहीं, और जीएसटी के बिना न तो व्यापारिक बिल जारी किए जा सकते हैं, न बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होती है और न ही औपचारिक कारोबार शुरू हो पाता है। ऐसे में अप्रैल में बनी नई कंपनियां कानूनी रूप से अस्तित्व में होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से निष्क्रिय बनी हुई हैं। कई उद्यमियों के निवेश अटके हुए हैं, ऑफिस शुरू नहीं हो पा रहे, भुगतान अटक रहे हैं और कारोबारी योजनाएं लटक गई हैं।

व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ी बेचैनी- पैन प्रक्रिया में आए इस बदलाव ने खासकर स्टार्टअप, नई फर्मों और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। व्यापारिक क्षेत्र में इसे लेकर असमंजस और चिंता का माहौल है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग को नई प्रक्रिया के संक्रमण काल में व्यावहारिक राहत देनी चाहिए, ताकि नई कंपनियों के पंजीयन और कारोबार शुरू होने की प्रक्रिया बाधित न हो। फिलहाल दस्तावेजी सख्ती और तकनीकी विलंब ने नए कारोबार की रफ्तार धीमी कर दी है।

महू तहसील की सरकारी जमीन पर बनेगा रिसोर्ट, गंभीर नदी के पुनर्जीवन को भी मिलेगी रफ्तार

इंदौर। प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में पर्यटन विकास निगम ने महू तहसील की सरकारी जमीन पर बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। पर्यटन विभाग ने महू क्षेत्र में स्थित लगभग सवा लाख स्क्वेयर फीट (1.1820 हेक्टेयर) सरकारी जमीन प्रशासन से मांगी है, जहां पर्यटन विभाग रिसोर्ट विकसित करेगा। इसके साथ ही महू क्षेत्र की गंभीर नदी के पुनर्जीवन और आसपास के धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्यों को भी गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार, महू तहसील के चोइथराम क्षेत्र स्थित सर्वे नंबर 371/4 और 372/2 की यह जमीन पर्यटन विभाग को आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्यटन विकास निगम की ओर से कलेक्टर को जमीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बाद महू अनुविभागीय अधिकारी ने प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

रिसोर्ट से बढ़ेगा पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ- पर्यटन विभाग का मानना है कि महू क्षेत्र में रिसोर्ट बनने से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों तक आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। महू और उसके आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में रिसोर्ट निर्माण के साथ यहां पर्यटन आधारित गतिविधियों का विस्तार होने की संभावना है।

धार्मिक स्थलों के विकास पर भी फोकस- प्रशासन का कहना है कि जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें रणजीत हनुमान लोक, बाणेश्वरी धाम, बिजासन लोक और अहिल्या लोक जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन स्थलों के विकास के साथ-साथ तालाबों, बावड़ियों और प्राचीन जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य धार्मिक आस्था के केंद्रों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है, ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

गंभीर नदी पुनर्जीवन को प्राथमिकता- कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की लंबित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की भी जानकारी ली। इस दौरान विशेष रूप से महू क्षेत्र की गंभीर नदी के पुनर्जीवन कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की सभी बावड़ियों, जल संरक्षण संरचनाओं और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि बारिश के मौसम में जल संरक्षण क्षमता बढ़ाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे जल संरक्षण के साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों का समग्र विकास हो सके।

उज्जैन मॉडल से इंदौर को उम्मीद- प्रशासन का मानना है कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद जिस तरह देश-विदेश से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसका सकारात्मक प्रभाव इंदौर संभाग पर भी पड़ा है। इसी तर्ज पर इंदौर और आसपास के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा ओम सर्किट के तहत उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर को जोड़ने की योजना भी क्षेत्रीय धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दे रही है। ऐसे में महू में प्रस्तावित रिसोर्ट और गंभीर नदी पुनर्जीवन परियोजना को इंदौर के पर्यटन विस्तार की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

समाज में जागरूकता फैलाने 17 से 21 मई तक शहर में निकलेगी सनातन जागृति यात्रा

इन्दौर। अतुल्य सेवा सनातन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा शहर में भव्य सनातन जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह 5 दिवसीय यात्रा 17 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। इस यात्रा का लक्ष्य समाज में जागरूकता फैलाना है, जिसमें मुख्य रूप से नशा मुक्ति, जीव हत्या पर रोक, पर्यावरण रक्षा, संस्कृति का संरक्षण, सनातन जागृति अभियान पर जोर दिया जाएगा। यह जानकारी आज इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष एवं युवा संत स्वामी अतुलानंद सरस्वती महाराज एवं संजय अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिदिन निकाली जाएगी, जिसमें रोजाना लगभग 1000 लोगों के शामिल होंगे। यह यात्रा प्रथम दिवस 21 मई को श्री सिद्धेश्वर धाम आश्रम (तेजाजी नगर) से शुरू होकर तीन इमली चौराहा स्थित मैदान पर समाप्त होगी। द्वितीय दिवस 22 मई को तीन इमली चौराहा से मूसाखेड़ी, पिपलियाहाना, बंगाली चौराहा, खजराना होते हुए रोबोट चौराहे पर समाप्त होगी। तृतीय दिवस 23 मई को रोबोट चौराहा से विजय नगर, पाटनीपुरा, मालवा मिल होते हुए मरीमाता क्षेत्र में समाप्त होगी।

चतुर्थ दिवस 24 मई को मरीमाता से 60 फिट रोड, कालानी नगर होते हुए बड़ा गणपति क्षेत्र में समाप्त होगी। पंचम दिवस 25 मई को बड़ा गणपति से खजूरी बाजार, राजवाड़ा, पंढरीनाथ होते हुए लालबाग, महू नाका के पास समापन होगा। स्वामी अतुलानंद सरस्वती महाराज ने प्रशासन से इस धार्मिक और सामाजिक यात्रा के सफल संचालन हेतु सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था के लिए सहयोग की अपील की है।

4 मई को किसानों का भोपाल में प्रदर्शन16 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध

इंदौर। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले प्रदेश के किसान अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर 4 मई को भोपाल कूच करेंगे। किसान पदाधिकारी का कहना है कि सरकार के कई नियम व्यावहारिक नहीं हैं, जिसमें नरवाई जलाने का सैटेलाइट सर्वे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। गेहूं सहित सभी फसलों को समर्थन मूल्य से नीचे मंडियों में नीलामी की बोली तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। महासंघ के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल व राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष त्रिलोक गोठी ने बताया कि 4 मई को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की जाएगी। मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा।

4 इंजन वाली डेमू फिर लेट, यात्रियों ने स्टेशन पर जताया विरोध

इंदौर। डॉ. अंबेडकर नगर (मऊ) से इंदौर होते हुए रतलाम जाने वाली डेमू ट्रेन (79309) एक बार फिर देरी से चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को यह ट्रेन करीब 1 घंटा 20 मिनट देरी से इंदौर पहुंची, जिसके बाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और लोगों ने नाराजगी जताई। यात्रियों का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने से यह ट्रेन लगातार अनियमित चल रही है। रोजाना देरी के कारण नौकरीपेशा, छात्र और अन्य यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई यात्रियों ने स्टेशन परिसर में शिकायत दर्ज कराते हुए ट्रेन को नियमित समय पर चलाने की मांग की। यह 15 कोच और 4 इंजन वाली स्पेशल डेमू ट्रेन दोपहर 1.25 बजे मऊ से इंदौर के लिए रवाना होती है और इंदौर पहुंचने के बाद दोपहर 3 बजे रतलाम के लिए प्रस्थान करती है। मंगलवार को यह ट्रेन मऊ से ही करीब डेढ़ घंटे की देरी से रवाना हुई, जिसका असर आगे के पूरे संचालन पर पड़ा। ट्रेन के इंदौर देरी से पहुंचने के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री ट्रेन का इंतजार करते रहे और समय पर जानकारी नहीं मिलने से परेशान नजर आए। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ट्रेन को तय समय पर चलाया जाए, ताकि रोजाना सफर करने वालों को राहत मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन को रास्ते में दूसरी ट्रेन की क्रॉसिंग के कारण रोका गया था। रेलवे की भाषा में इसे वीपीटी (वाहिकल पोजिशन/पासिंग टाइम) की स्थिति माना जाता है, जब किसी ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए रोका जाता है। अधिकारियों ने ट्रेन के लेट होने की पुष्टि की है।

इंदौर हादसे से भी नहीं लिया सबक: 50 गांवों में "जहर" बन रहा पानी, फाइलों में सिमटी सफाई व्यवस्था

इंदौर । एक तरफ सरकार ग्रामीण विकास और स्वच्छता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी ओर जबलपुर जनपद पंचायत के करीब 50 गांवों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सालीवाड़ा गौर, नीमखेड़ा, खमरिया सहित कई गांवों में दूषित पानी लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है।

इंदौर जैसी घटनाओं से भी नहीं जागा प्रशासन

इंदौर में दूषित पानी से हुई गंभीर घटनाओं के बाद भी यहां का स्थानीय प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। गांवों में नालियों की सफाई नियमित नहीं हो रही, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। यही पानी लीकेज पाइपलाइनों के जरिए घरों तक पहुंच रहा है—सीधे शब्दों में कहें तो लोग "जहर" पीने को मजबूर हैं।

पुरस्कार पाने वाली पंचायत, लेकिन पानी बदहाल सालीवाड़ा गौर पंचायत ने राजस्व वसूली में जिले में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन विडंबना यह है कि यहां के ग्रामीणों को साफ पानी तक नसीब नहीं। नल-जल योजना का पानी दूषित पाइपलाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त नालियों का गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा क्लोराइड युक्त पानी से बीमारियों का खतरा खमरिया और आसपास के गांवों में लोग क्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कारणः सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असरलोग अब वैकल्पिक पानी की तलाश में भटक रहे स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर सवाल ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। कुओं में ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं डाला जा रहा जल स्रोतों की जांच नहीं संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा सफाई के नाम पर खर्च, जमीन पर गंदगी हर महीने 40–50 हजार रुपये सफाई पर खर्च होने का दावा, लेकिन हकीकतः नालियां कचरे से पटी गंदा पानी सड़कों पर बह रहा मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन पर भरोसा खत्म पंचायत सचिव राजेश तिवारी और सरपंच सौरभ राय "शेंकी" सफाई और पाइपलाइन सुधार के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। यह मामला सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। जब राजस्व वसूली में अव्वल पंचायत अपने ही लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही, तो यह सिस्टम की गंभीर विफलता को उजागर करता है। सवाल सीधा हैः क्या "हर घर नल-जल" सिर्फ कागजों में ही बह रहा है?

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दिया गया इंदौर के भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण

इंदौर (प्रदीप जैन)। तिलक नगर स्थित राजेंद्रसूरी गुरु मंदिर में आचार्य श्रीमद्विजय हितेशचंद्र सूरीश्वरजी म.सा. की पावन निश्रा में 2 से 4 मई 2026 तक आयोजित होने वाले भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु आज भोपाल में डॉ. मोहन यादव को ससम्मान आमंत्रण प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री को आमंत्रण देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से मेघराज जैन,अनूप कटारिया, संजय मोदी ,प्रेम कमल वागरेचा एवं सौरभ जैन शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आयोजन में पधारकर धर्मलाभ लेने एवं समारोह की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया। इस दौरान महोत्सव की धार्मिक गरिमा, कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं समाजजनों की तैयारियों की जानकारी भी दी गई। गौरतलब है कि इंदौर में 29 अप्रैल से 4 मई तक मंगल प्रवेश, नवकारसी, प्रवचन, जाजम वरघोड़ा तथा प्रतिमा प्रतिष्ठा सहित अनेक भव्य धार्मिक आयोजन होंगे, जिससे शहर का वातावरण पूर्णतः धर्ममय रहेगा। इस आयोजन का संयुक्त संचालन श्री सौधर्म बृहत्तपागच्छीय त्रिस्तुतिक जैन श्रीसंघ, श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट, श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, श्री राजेंद्र सूरी आराधना भवन एवं श्री पार्श्वनाथ राजेंद्र प्रतिष्ठा महोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है।

हाईटेक सिस्टम बना सिरदर्द, इंदौर में आईटीएमएस की गलती से निर्दोष वाहन मालिक पर कट गया चालान

Indore। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अब कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जिस तकनीक से ट्रैफिक सुधार और नियमों के बेहतर पालन की उम्मीद की जा रही थी, वही तकनीकी खामियों के चलते निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। हाल ही में सामने आया एक मामला इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, जिसमें एक व्यक्ति के नाम ऐसा चालान जारी कर दिया गया, जिसकी गाड़ी घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी।

मामला तब सामने आया जब आईटीएमएस कैमरे ने एक दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट के चलते रिकॉर्ड किया। कैमरे द्वारा वाहन की नंबर प्लेट को पढ़ते समय एक अंक की मामूली गलती हुई, लेकिन इसका परिणाम बेहद गंभीर रहा। सिस्टम ने गलत नंबर के आधार पर चालान जनरेट कर दिया, जो किसी दूसरे वाहन मालिक के नाम पर जारी हो गया। हैरानी की बात यह है कि चालान में न सिर्फ वाहन नंबर गलत है, बल्कि वाहन की कंपनी और मालिक की जानकारी भी पूरी तरह अलग है, जो दस्तावेजों में साफ दिखाई देती है। जानकारी के अनुसार, पलासिया क्षेत्र में बिना हेलमेट के जिस वाहन को कैमरे ने रिकॉर्ड किया, उसका नंबर एमपी09-यूएक्स-0809 था, लेकिन चालान एमपी09-यूएक्स-0909 के नाम पर जारी कर दिया गया। विजयनगर निवासी पीड़ित ने बताया कि दोनों वाहनों की कंपनी और मॉडल तक अलग-अलग हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि गलती सिस्टम की है। इसके बावजूद पीड़ित को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

पीड़ित जब एमटीएच कम्पाउंड स्थित यातायात थाने के आईटीएमएस सेंटर पहुंचा और अपनी समस्या बताई, तो उसे तत्काल समाधान देने के बजाय एक टेबल से दूसरे टेबल तक घुमाया गया। अंततः उसे ही आवेदन देने और अपने वाहन के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया।

यह स्थिति उस समय और भी विडंबनापूर्ण हो जाती है, जब स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि चालान में दर्ज वाहन और वास्तविक वाहन में कोई समानता नहीं है। इसके बावजूद जिम्मेदारी नागरिक पर ही डाल दी गई है। इस तरह की घटनाएं केवल एक-दो मामलों तक सीमित नहीं हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें तकनीकी त्रुटियों के कारण गलत चालान जारी किए गए। कुछ मामलों में तो दूसरे शहरों के वाहन मालिकों ने शिकायत की कि उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट किसी अन्य वाहन पर लगाकर इंदौर में चलाई जा रही है और चालान उनके पते पर भेजे जा रहे हैं। इन मामलों में लोगों को अपनी समस्या लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं सुनवाई हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि आईटीएमएस जैसी तकनीक तभी प्रभावी साबित हो सकती है, जब इसकी सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। नंबर प्लेट रीडिंग में छोटी सी गलती भी किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में सिस्टम में सुधार और निगरानी की सख्त आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों को रोका जा सके। शहर में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाए गए कैमरे और ऑटोमेटेड चालान प्रणाली का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। लेकिन जब यही सिस्टम गलत तरीके से काम करने लगे, तो यह आम लोगों के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है। नागरिकों का कहना है कि अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बिना गलती के चालान भरने के बजाय लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर में लागू की गई हाईटेक व्यवस्था पूरी तरह से भरोसेमंद है। अगर सिस्टम में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर करे और आम नागरिकों को इस तरह की अनावश्यक परेशानियों से बचाए।

बड़े पार्टनर होने का अनुभव कैसा है?

● यशस्वी ने कहा 'मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा हूं। मैं अभी भी बहुत युवा हूं'

चंडीगढ़ (एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर पंजाब किंग्स के विजयी अभियान को रोक दिया। फ्रेंचाइजी के जाने-माने चेहरे जायसवाल ने अपनी 'ऑरेंज कैप' साथी खिलाड़ी और 15 साल के ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी को सौंपी। जब ब्रॉडकास्टर ने जायसवाल से पूछा, 'बड़े पार्टनर होने का अनुभव कैसा है?' इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा हूं। मैं अभी भी बहुत युवा हूं। थोड़ा और सोच-समझकर बोलते हुए जायसवाल ने माना कि उम्र का यह अंतर उनके लिए एक अनोखी स्थिति थी। उन्होंने कहा, लेकिन हां, वह काफी छोटा है। इसलिए, सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में क्या कहूं। बेशक यह बहुत बढ़िया है। मुझे उसके साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आया और वह बहुत शानदार खेल रहा है। इसलिए जब मैं दूसरे छोर से उसे गेंद पर जोरदार शॉट लगाते देखता हूं, तो मुझे हमेशा खुशी होती है।

न्यूजीलैंड ने महिला टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

वेलिंगटन (एजेंसी)। न्यूजीलैंड ने पिछले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में खिताबी जीत वाली टीम में शामिल कुल 10 खिलाड़ियों को इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है।

न्यूजीलैंड ने बुधवार को स्टार ऑलराउंडर मेली केर को टीम का कप्तान बनाया। इसी के साथ मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड टी-20 विश्व कप के लिए अपनी टीम का घोषणा करने वाली दूसरी टीम बन गई। कीवी टीम में अनुभव और युवाओं का अच्छा मेल है, जिसमें अनुभवी सूजी बेट्स और डिवाइन अपने 10वें टी-20 विश्व कप में

खेलेंगी, जबकि नई खिलाड़ी नेन्सी पटेल और बल्लेबाज इजी शार्प का आईसीसी टूर्नामेंट में अपने पहले अनुभव के लिए टीम में स्वागत किया गया है। पहली पसंद की स्पिनर ईडन कार्सन अपनी लंबे समय से कोहनी की चोट के कारण टीम में नहीं चुनी जा सकीं।

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयर ने कहा, मेरा मानना है कि हमें एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड टीम मिली है जिसमें एक्सपीरियंस और रोमांचक युवा प्रतिभा का मिश्रण है। हमने पिछले 12 महीनों में अपनी बैटिंग डेप्थ को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की है, खासकर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी हालिया होम सीरीज में इसका फायदा देखने को मिला है। न्यूजीलैंड टी-20 वर्ल्डकप में ग्रुप 2 में होगा और नॉकआउट स्टेज से पहले इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलेगा।

विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड टीम – मेली केर (कप्तान), सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, जेस केर, रोजमेरी मेयर, नेन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लिमर, इजी शार्प और ली ताहुहू।

एआईएफएफ यूथ लीग

पंजाब एफसी का जलवा बरकरार, फाइनल में 3-0 से शानदार जीत

नईदिल्ली (एजेंसी)। पंजाब एफसी ने एआईएफएफ एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड करते हुए फाइनल में जिंक फुटबाल एकादमी को 3-0 से हराया। गढ़शंकर के रामसर साहिब स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब स्क्वॉड ने दूसरे हाफ में दमदार प्रदर्शन किया।

10 मिनट में मैच खत्म – दूसरे हाफ में महज 10 मिनट के अंदर पंजाब स्क्वॉड ने तीन गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। 69वें मिनट में कृष शोरम ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके ठीक एक मिनट बाद 70वें मिनट में कप्तान विशाल यादव ने गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया।

तीसरे गोल से पक्की जीत – पंजाब एफसी का आक्रमण यहीं नहीं रुका और 79वें मिनट में थोग्राम रिषीकांत सिंह ने तीसरा गोल दागकर जीत पूरी तरह सुनिश्चित कर दी।

पहले हाफ में बराबरी की टक्कर – पहले हाफ में पंजाब स्क्वॉड ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा और लगातार हमले किए, लेकिन जिंक फुटबाल एकाडमी के गोलकीपर स्मारनिक थापा ने कई शानदार बचाव किए।

अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं

अभिनेत्री करिश्मा कपूर लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि, उनका कहना है कि वो अब समय को ज्यादा महत्व देती हैं और चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ही काम करना चाहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने करियर और काम के प्रति अपने जुनून को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं।

अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं

करिश्मा कपूर ने दशकों से इंडस्ट्री को करीब से देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज काम जुनून और उद्देश्य से जुड़ा है। मैं इंडस्ट्री में पली-बढ़ी हूं और मुझे कमर्शियल ब्लॉकबस्टर से लेकर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों तक, हर तरह की भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य मिला है। अब हर जगह मौजूद रहने के बजाय मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं। अभिनेत्री स्वीकार करती हैं कि अब समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लगातार काम करने और एक सेट से दूसरे सेट पर जाने की वजह से काफी भागदौड़ रहती थी। अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं। मैं सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर प्रोजेक्ट के लिए समय निकालना सार्थक हो और साथ ही परिवार को भी पर्याप्त समय मिल सके। स्क्रिप्ट तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही लोग और कहानी के पीछे का मकसद भी मायने रखता है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि बड़े पर्दे का अपना ही जादू है, यहीं से मैंने शुरुआत की थी और यह हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। लेकिन मुझे यह भी पसंद है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कहानी कहने का तरीका कैसे विकसित हुआ है। वेब मुश्किल कहानियों और अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए मौका देता है। मेरे जैसी किसी के लिए जो आगे क्या करना है, इस बारे में सोच-समझकर फैसला लेती है यह एक बेहतरीन क्षेत्र है। हालांकि, मैं बड़े पर्दे को कभी नहीं छोड़ूंगी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो करिश्मा कपूर आखिरी बार साल 2024 में आई मर्डर-मिस्ट्री फिल्म 'मर्डर मुबारक' में नजर आई थीं। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी।

'कॉकटेल 2' में होगी दीपिका पादुकोण की एंट्री, वेरोनिका के किरदार में करेंगी वापसी?

दीपिका पादुकोण बीते दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद सुर्खियों में आ गई थीं। इस बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने वेरोनिका के किरदार में वापसी कर सकती हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने 'कॉकटेल' के किरदार में ही कैमियो कर सकती हैं। जानिए आखिर क्यों उठीं ऐसी चर्चाएं हैं और क्या है सच्चाई?

ऐसे शुरू हुई चर्चाएं

दरअसल, रेडिट पर एक पोस्ट के बाद से ही फैंस के बीच इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में 2012 की 'कॉकटेल' के लोकप्रिय और बिंदास किरदार वेरोनिका में कैमियो करेंगी। पोस्ट के अनुसार, दीपिका कुछ महीने पहले मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस गई थीं। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह मुलाकात 'महावतार' से जुड़ी थी। लेकिन पोस्ट में दावा किया गया है कि दरअसल उन्हें सीक्वल में वेरोनिका के किरदार में आने के लिए बार-बार संपर्क किया जा रहा था। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और उसी दौरान अपने हिस्से की शूटिंग भी कर ली।

'कॉकटेल' में दीपिका ने किया था वेरोनिका का किरदार

वेरोनिका दीपिका के सबसे चर्चित किरदारों में से एक है। 2012 में आई 'कॉकटेल' में वेरोनिका अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा (डायना पेंटी) और उसके लवर गौतम (सैफ अली खान) के साथ लव ट्रायंगल में फंस जाती है। हालांकि, अभी तक दीपिका के फिल्म में कैमियो करने की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस चर्चा ने 'कॉकटेल 2' को लेकर नई हलचल मचा दी है, जो पहले से ही अपनी कास्ट, संगीत और माहौल के लिए ध्यान आकर्षित कर रही है।

19 जून को रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 2012 की 'कॉकटेल' का सीक्वल है। हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग होने की बात कही जा रही है। फिल्म में रोमांस, प्यार और रिश्तों को एक अलग तरह से दिखाया जाएगा। हाल ही में फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया है, जिसे पसंद भी किया जा रहा है। 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मृणाल ठाकुर की जगह श्रुति हासन होंगी 'पेद्दी' का हिस्सा

राम चरण की अदाकारी वाली फिल्म 'पेद्दी' जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा में है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। खबरें हैं कि फिल्म के निर्माता श्रुति हासन को लेकर एक स्पेशल गाने की योजना बना रहे हैं।

क्या 'पेद्दी' में कैमियो करेंगी श्रुति हासन?
गल्ट के मुताबिक श्रुति हासन को 'पेद्दी' में एक स्पेशल कैमियो रोल के लिए साइन किया जा सकता है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर रनवे सा एहसास: स्मार्ट कंट्रोल रूम

मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे में पहुंचें

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-नोएडा से प्रयागराज की दूरी को कम करने वाले बहुप्रतिक्षित गंगा एक्सप्रेसवे को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को सौंप देंगे। 594 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाली गंगा एक्सप्रेस की अनुमानित लागत करीब 36,402 करोड़ रुपये बताई जा रही है। स्मार्ट कंट्रोल रूम वाली सुविधा के साथ इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग के दौरान नींद की झपकी आने पर जगाने वाले फीचर का भी ध्यान रखा गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत कई जिलों से होकर गुजर रहा है। इससे इन संबंधित जिलों के लोगों को आवाजाही में आसानी तो होगी साथ ही रोजगार के भी नए अवसरों की राह खुलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी मिलेगी।

दावा किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी और समय दोनों को आधा कर देगा।

जहां पहले यही दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे। वहीं, अब यह लंबा सफर महज 5 से 6 घंटे में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे एवं नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मार्ग को जोड़ रहा है। साथ ही, हरिद्वार की कनेक्टिविटी को भी आसान बनाएगा। यही कारण है कि इसकी चौड़ाई भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन भी की जा सकती है। आशा जताई जा रही है कि इससे उद्योग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में आने वाले समय में यह आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आपातकालीन सेवाएं, कैमरा निगरानी और एयरस्ट्रिप जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ यात्रियों की दूरी को ही कम नहीं करेगा यह रोजगार के अनेक अवसर भी मुहैया कराएगा। इसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके किनारे 12 औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की योजना है, जिनमें लगभग 47,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।

दिल्ली में बिना हेलमेट की सवारी बन रही मौत का सबब, 15 अप्रैल तक 188 बाइकर्स की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए बेखौफ सड़कों पर मोटरसाइकिल और स्कूटी दौड़ा रहे हैं। हालात यह हैं कि कई वाहन चालक न सिर्फ बिना हेलमेट सफर कर रहे हैं, बल्कि चलते वाहन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष 15 अप्रैल तक सड़क हादसों में 188 दोपहिया वाहन चालकों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर्फ चालक ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी इस लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। इसी अवधि में लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाने वालों की चपेट में आने से 62 लोगों की जान चली गई। इससे साफ है कि बिना हेलमेट और असावधानी से वाहन चलाना न सिर्फ चालक के लिए, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के

लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है।

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में बिना हेलमेट वाहन चलाने के बढ़ते चलन को देखते हुए यातायात पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 15 अप्रैल तक 4.24 लाख चालान काटे जा चुके हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि केवल चालान काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। जब तक लोग खुद अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हादसों में कमी लाना मुश्किल होगा।

सड़क सुरक्षा अभियान का भी नहीं दिख रहा असर

यातायात पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेजों, मॉल व अन्य सार्वजनिक जगहों पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है, जिससे सड़क हादसों में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सके।

दिल्ली विधानसभा में गूंजा बेसहारा गायों का मुद्दा, सड़क जाम और हादसों पर विधायकों की सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़कों पर बेसहारा गायों के जमावड़े से जनता ही नहीं, विधायक भी परेशान हैं। मंगलवार को विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत अनेक विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। विधायक श्याम शर्मा, कुलवंत राणा एवं हरीश खुराना ने इस पर प्रमुखता से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि सड़कों पर जहां तहां बेसहारा गायों का झुंड देखने को मिल जाता है। दिन में यह झुंड ट्रैफिक जाम की वजह बनता है और रात के अंधेरे में हादसों का सबब। इन विधायकों का कहना था कि उनके कार्यालय में भी हर रोज इस संदर्भ में शिकायतें आती रहती हैं। इन सभी विधायकों की ओर से इस समस्या का गंभीरता से कोई निदान निकालने की मांग भी की गई। मांडल टाउन से विधायक अशोक गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशीले पदार्थों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि खुलेआम नशे का कारोबार बढ़ रहा है और पुलिस भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने खिड़की एक्सटेंशन और प्रेस एनक्लेव के बीच ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने यहां से आउटर रिंग रोड तक लिंक रोड बनाने की मांग रखी। विधायक संजय गोयल ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग रखी ताकि लंबित मामले निपटाए जा सकें। उनका कहना था कि न्याय देरी से मिलना नहीं मिलने के बराबर है। इसलिए इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। विधायक कुलदीप सोलंकी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया और इसे लेकर सख्ती करने की मांग उठाई। विधायक गजेंद्र दराल ने अपने इलाके में पेयजल किल्लत की समस्या उठाई। उन्होंने मांग की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल्द से जल्द जलापूर्ति की कमी दूर की जाए और पानी की लाइनें भी बदली जाएं। डा अनिल गोयल ने पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का मुद्दा रखा। साथ ही पूरे क्षेत्र का एक सर्वे करवाकर यहां की व्यवस्था सुधारने को यथावश्यक कदम उठाने की मांग की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित उम्मीदवार को जेईई एडवांस्ड-2026 में बैठने की दी इजाजत

नई दिल्ली, एजेंसी। आइआइटी में प्रवेश स्वीकार करने के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेईई एडवांस्ड–2026 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी और आयोजन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर उसे टिकट जारी करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि आप इस संस्थान का महत्व नहीं समझते और आइआइटी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। कक्षा एक से ही बच्चों की यह महत्वाकांक्षा होती है कि उन्हें आइआइटी में सीट मिले। पीठ ने कहा कि यह बच्चों का सपना होता है और अदालत इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि उम्मीदवार कल किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेगा और यह प्रतिभा पलायन होगा। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 17 मई 2026 को होने वाली प्रस्तावित परीक्षा, जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठने के लिए अब से एक सप्ताह के भीतर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टिकट जारी कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, तो उसकी याचिका निष्फल हो जाएगी और यदि वह मुकदमा हार जाता है, तो उसकी परीक्षा रद घोषित की जा सकती है। उम्मीदवार की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता तन्वी दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल जेईई (मेन्स) 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और जेईई (एडवांस्ड) 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की, लेकिन किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया। अदालत को बताया गया कि काउंसलिंग के छठे दौर में, आइआइटी गुवाहाटी में एक सीट को स्वीकृत मान लिया गया और जुलाई 2025 में उसकी सहमति के बिना उसे आवंटित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यद्यपि उसने आइआइटी गुवाहाटी में शामिल होने की अनिच्छा तुरंत बता दी थी, फिर भी आयोजन समिति ने अधिकारियों ने उन्हें इस वर्ष आइआइटी प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोक दिया क्योंकि वे जेईई एडवांस्ड 2026 के मानदंड ए–पांच के अनुसार पात्र नहीं है।

गृह विभाग की फंडिंग खत्म होने की कगार पर, टीएसए कर्मचारियों के वेतन पर भी खतरा; हवाई सुरक्षा पर असर की आशंका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक बार फिर सरकारी फंडिंग को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और उससे जुड़े अहम विभागों के पास कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए फंड जल्द ही खत्म हो सकता है। इससे देश की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रबंधन और बजट कार्यालय ने सांसदों को एक मेमो भेजकर बताया है कि परिवहन सुरक्षा प्रशासन और अन्य कर्मचारियों की सैलरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश से दिया गया पैसा मई तक खत्म हो जाएगा। इससे एयरपोर्ट संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि अगर जल्द ही बजट पारित नहीं किया गया तो सुरक्षा कर्मियों के वेतन और संचालन दोनों पर संकट गहरा जाएगा। मेमो में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा को सीनेट द्वारा पिछले हफ्ते पास किए गए बजट प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देनी चाहिए, ताकि विभाग को पूरा फंड मिल सके। मेमो के अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी विभाग जल्द ही जरूरी फंड से खत्म हो जाएगा, जिससे जरूरी कर्मचारियों और कामकाज पर खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिकी

संसद में बजट को लेकर राजनीतिक खींचतान लगातार जारी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति न बनने के कारण कई महत्वपूर्ण विभागों की फंडिंग अटक गई है। इस बीच, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी आंतरिक विवाद के चलते बजट प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, जिससे पूरा सिस्टम लगभग ठप जैसा हो गया है। ट्रंप प्रशासन का यह दबाव हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के लिए मददगार साबित हो सकता है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुत कम बहुमत है और पार्टी के अंदर कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं, जिनमें होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग भी शामिल है। इसी वजह से सदन का कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रतिनिधि सभा बुधवार को सीनेट द्वारा पास किए गए बजट प्रस्ताव पर वोट करेगी। यह प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे विभाग को पूरी फंडिंग मिल सकेगी। प्रशासन ने रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी है कि अगर वे इस प्रस्ताव में बदलाव करते हैं तो बिल पास होने में देरी हो सकती है। मेमो में यह भी कहा गया है कि ष्ठ॥स् के लिए फंडिंग बहाल करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। इसका कारण हाल की एक घटना है, जब बंदूक और चाकू लेकर एक व्यक्ति व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर में घुसने की कोशिश कर रहा था।

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की संसद में बड़ी जीत

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने संसद में एक महत्वपूर्ण वोट जीत लिया है। सांसदों ने उनके खिलाफ नैतिकता जांच शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव के विरोध में 335 और पक्ष में 223 वोट पड़े। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्टार्मर ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने के मामले में संसद को गुमराह किया है। मैंडेलसन के संबंध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से रहे हैं। इस विवाद के कारण स्टार्मर पिछले कई महीनों से भारी दबाव में थे। वोटिंग से पहले स्टार्मर ने अपनी लेबर पार्टी के सांसदों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने इस प्रस्ताव को विरोधियों का राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों से ठीक पहले उन्हें काम करने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। दूसरी ओर, विपक्षी नेता केमी बेडनोच ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सांसद इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे रहे हैं, उन्हें अपने विवेक की जांच करनी चाहिए। इस बीच, स्टार्मर के पूर्व मुख्य सलाहकार मॉर्गन मैकस्वीनी ने भी इस नियुक्ति को एक गंभीर गलती बताया और इसकी जिम्मेदारी ली। भले ही स्टार्मर ने यह वोट जीत लिया है।